करेंट अफेयर्स राजस्थान

जनवरी 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **5**

- 'The planning Period of Covid Health Consultants and Covid Health Assistants has been Extended by Three Months' 5
- शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का 29वाँ सम्मान समारोह 5
- ज़िलास्तरीय इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन 6
- निर्वाचन विभाग ने किया प्रदेश के 200 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6
- नागौर, चूरू तथा अजमेर में नवीन राजस्व ग्राम घोषित 7
- जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिये 6872.28 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी मिली 7
- नागौर को मिला 24वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड 8

The Vision

नोट :

- सरकार के तीन साल की उपलब्धियों पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ 8
- ज्ञानदूत 2.0 का ऑनलाइन उद्घाटन 9
- जी.एस.टी. एडवान्स्ड ऐनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ 10
- राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में 405 पशुपालकों को किया गया सम्मानित 10
- 'अंगदान-महादान' संदेश लिखी पतंगों का विमोचन 11
- राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा का शिलान्यास 11
- मुख्यमंत्री ने किया गांधी बधिर महाविद्यालय जोधपुर का उद्घाटन 11
- प्रदेश के सभी ज़िलों में पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं को मिला 'एनएबीएल एक्रीडिशन' 12
- 29वीं राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का वर्चुअल शुभारंभ 13
- 'जागती जोत' के 'पंडित भरत व्यास विशेषांक' का विमोचन 13
- उद्योग मंत्री ने की 'स्वस्थ बेटी अभियान' की शुरुआत 14

नोट :

➢ राजस्थान की गौरी माहेश्वरी एवं आनंद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 14

➢ राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 15

➢ उदयपुर के नाथद्वारा में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ 15

➢ राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास 16

➢ परिवहन आयुक्त ने किया डॉक्यूमेंट्री 'हर जीवन अनमोल है' को रिलीज 16

➢ प्रदेश में ई-दाखिल की शुरुआत 16

नोट :

राजस्थान

'The planning Period of Covid Health Consultants and Covid Health Assistants has been Extended by Three Months'

Why in News

- On December 31, 2021, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot approved the proposal to extend the planning period of Covid Health Consultants and Covid Health Assistants by three months from January, 2022 to March, 2022 in view of the present situation of Covid and the possibility of a third wave.

Key Points

- With this decision of the Chief Minister, the work of prevention of third wave of Covid-19, limiting the spread of infection and door-to-door survey and distribution of medicines will be conducted smoothly in the state.
- The Chief Minister has also given approval to pay the honorarium of Covid Health Consultants and Covid Health Assistants from grants received to Panchayati Raj Institutions or local body institutions under the State Finance Commission like the 15th Finance Commission of the Center.

शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का 29वाँ सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

- 2 जनवरी 2022 को राजस्थान के शिक्षा विभाग का 29वाँ राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान राज्य भर के 40 कार्मिकों का सम्मान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि बीकानेर के शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विभागीय परीक्षा कार्यालय को भी मज़बूती प्रदान की जाएगी।
- डॉ. कल्ला ने पुरस्कार की प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और ग्यारह हजार रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया।
- कार्यक्रम का परिचय देते हुए वरिष्ठ सहायक सत्यनारायण व्यास ने बताया कि मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का सम्मान यह परंपरा वर्ष 1990 में शुरू हुई। अब तक 898 कार्मिकों को इस सम्मान से नवाज़ा गया है।

ज़िलास्तरीय इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को इनवेस्ट राजस्थान 2022 समिट से पहले जयपुर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में ज़िलास्तरीय इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। इसमें कुल 23 हज़ार 528 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू और एलओआई हुए, इससे प्रदेश में 1 लाख 13 हज़ार से अधिक रोज़गार का सृजन होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर शकुंतला रावत ने बताया कि इनवेस्ट राजस्थान समिट को इस बार नए तरीके से कराया जा रहा है, ताकि अधिक-से-अधिक निवेश प्रस्तावों को ज़मीन पर उतारा जा सके।
- इसके लिये पहली बार सरकार सम्मेलन से पहले ज़िलों में भी ऐसे निवेश सम्मेलन करा रही है। सभी ज़िलों में मुख्य समिट से पहले एक माह तक ये सम्मेलन किये जाएंगे।
- उद्योग मंत्री ने बताया कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिये एमओयू से लेकर ज़मीन खरीदने तक की प्रक्रिया यहीं तय कर ली जाएगी। निवेश जब पक्का हो जाएगा तो उद्घाटन शिलान्यास के स्तर पर ही इसे मुख्य समिट तक लाया जाएगा।
- इस अवसर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने और स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये भी एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इसके अलावा सोलर पैनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, जेम्स और ज्वेलरी, प्लाईवुड, होटल और हॉस्पिटल, टेक्सटाइल और गारमेंट से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिये एमओयू तथा एलओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

निर्वाचन विभाग ने किया प्रदेश के 200 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को निर्वाचन विभाग ने राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 14 लाख 22 हज़ार 968 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इनमें 7 लाख 20 हज़ार 223 पुरुष और 7 लाख 2 हज़ार 745 महिलाएँ हैं। इस प्रकार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2.87 प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई।
- उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन की तिथि तक राज्य में कुल 5 करोड़ 9 लाख 43 हज़ार 21 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2 करोड़ 65 लाख 32 हज़ार 787 पुरुष एवं 2 करोड़ 44 लाख 10 हज़ार 234 महिला मतदाता सम्मिलित हैं।
- पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 23 हज़ार 869 विशेष योग्यजनों का भी पंजीकरण किया गया। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में कुल 5 लाख 26 हज़ार 991 विशेष योग्यजन मतदाता पंजीकृत हैं।
- पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन माध्यम से कुल 28 लाख 46 हज़ार 506 आवेदन-पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जो कि संपूर्ण देश में सर्वाधिक है। 18 वर्ष की आयु के 3 लाख 26 हज़ार 103 युवा मतदाताओं एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के 7 लाख 78 हज़ार 718 मतदाताओं द्वारा अपने स्वयं के मोबाइल नंबर की सूचना आवेदन-पत्र में देकर मतदाता सूची में पंजीकरण करवाया गया है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रकाशित मतदाता सूची में 80 या 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल 13 लाख 17 हज़ार 741 मतदाता पंजीकृत हैं।
- इसी प्रकार से विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5 लाख 26 हज़ार 991 विशेष योग्यजन मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1 लाख 42 हज़ार 827 सेवा नियोजित मतदाता अंतिम भाग में पंजीकृत हैं।

नोट :

नागौर, चूरू तथा अजमेर में नवीन राजस्व ग्राम घोषित

चर्चा में क्यों?

- 5 जनवरी, 2022 को राजस्थान सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी कर चूरू, अजमेर, नागौर ज़िले के मजरों एवं ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नागौर ज़िले की तहसील कुचामन सिटी के मूल राजस्व ग्राम सबलपुरा को नवीन राजस्व ग्राम नाडापुरा एवं सिंधपुरा को शहीद रामेश्वर नगर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- इसी प्रकार अजमेर की तहसील भिनाय के पाडलिया मूल राजस्व ग्राम को गोरधनपरा तथा गुढ़ाखुर्द को इंद्रपुरा नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अजमेर में ही सोमलपुर मूल राजस्व ग्राम को आगला कांकड, शाही, चंदवाला तथा डाली नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- अधिसूचना के अनुसार चूरू ज़िले के रामदेवरा तथा जसरासर राजस्व ग्राम को जसरासर बास नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- इन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण के लिये तथा इनकी पृथक्-पृथक् जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शे अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये संबंधित ज़िलों के कलक्टर को अधिकृत किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में चूरू के पटवार मंडल जसरासर एवं नाकरासर का पुनर्गठन किया गया है। जसरासर गाँव के क्षेत्राधिकार में अब जसरासर, रामपुरा बास, दुधवामीठा, जसरासर बास राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे तथा नाकरासर गाँव में नाकरासर तथा रामदेवरा राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया जाएगा।

जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिये 6872.28 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी मिली

चर्चा में क्यों?

- 5 जनवरी, 2022 को राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिये 6,872.28 करोड़ रुपए लागत की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इन योजनाओं से 27 जिलों में स्थित 3,213 गाँवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं में से 5 बहु ग्राम प्रमुख परियोजनाएँ और शेष एकल ग्राम योजनाएँ हैं।
- हर ग्रामीण परिवार को पीने का स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने और महिलाओं और लड़कियों को दूर से पीने का पानी लाने के कष्ट से मुक्ति दिलाने के विजन को मूर्त रूप देने के लिये जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में राजस्थान को 2,345.08 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की गई थी।
- इस वर्ष केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लागू करने के लिये राज्य को 10,180.50 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। यह राशि पिछले साल के आवंटन से चार गुणा अधिक है।
- 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राज्य में केवल 11.74 लाख (11.57 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही थी। वर्तमान में राज्य के 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख (21.92 प्रतिशत) परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राजस्थान में 58,363 स्कूलों (67 प्रतिशत) और 28,959 आंगनबाड़ी केंद्रों (54 प्रतिशत) को उनके परिसरों में नल से पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है।

- एसएलएसएससी की 31वीं बैठक में 2,885 स्कूलों और 418 आंगनबाड़ी केंद्रों को नल से जल उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में इस मिशन की शुरुआत में देश के कुल 19.2 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) को ही नल से जल की आपूर्ति हो रही थी। वर्तमान में पूरे देश में 8.77 करोड़ (45.57 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है।
- गोवा, तेलंगाना, हरियाणा राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुच्चेरी, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल के कनेक्शन सुनिश्चित किये गए हैं।

नागौर को मिला 24वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 7 जनवरी, 2022 को नागौर ज़िला के अभियान सिलिकोसिस केयर को 'एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन' केटेगरी में 24 वें नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान, एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह व तेलंगाना के नगरीय निकाय, शहरी विकास उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के सचिव वी. श्रीनिवास ने ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को हैदराबाद में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया।
- एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन की सिल्वर कैटेगरी में दिये गए इस अवार्ड के तहत नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी व उनकी टीम को पुरस्कारस्वरूप प्रशस्ति-पत्र और एक लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया।
- गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय स्तर का ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार देश के सभी 748 ज़िलों में ई-गवर्नेंस पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले को दिया जाता है। इसके तहत चार चरणों में संपूर्ण परीक्षण के बाद एक जटिल प्रक्रिया से ज़िले का चयन किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त त्वरित सहायता राशि, पेंशन, पालनहार योजना व खाद्य सुरक्षा का लाभ दिये जाने को लेकर नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से अभियान 'सिलिकोसिस केयर' चलाया गया। इसके तहत नागौर ज़िले में 2058 जीवित सिलिकोसिस मरीज़ों तथा 360 दिवंगत सिलिकोसिस मरीज़ों के परिजनों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं का लाभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकल प्रारूप में डाटाबेस तैयार कर दिया गया।
- इस नवाचार को मॉडल मानते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान (गुप-1) विभाग ने भी जारी किये थे।
- विदित हो कि अभियान सिलिकोसिस केयर के लिये गवर्नेंस नॉउ टीम की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन इन हेल्थ केयर कैटेगरी में दिया जाने वाला चौथा डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन अवार्ड-2021 भी नागौर ज़िला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को गत नवंबर 2021 में प्रदान किया गया था।

सरकार के तीन साल की उपलब्धियों पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 11 जनवरी, 2022 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री एवं करौली ज़िला प्रभारी अशोक चांदना ने करौली के सूचना केंद्र के बाहर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 'आपका विश्वास हमारा प्रयास'विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन-जन के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, जिसके तहत विगत तीन वर्षों में फ्लैगशिप योजनाओं एवं आधारभूत विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित व पात्र वर्गों को लोक कल्याण की योजनाओं का समुचित लाभ प्रदान किया गया है।
- इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा ज़िले में विभिन्न क्षेत्रों में किये गए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।
- ज़िला प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात् ज़िले में विगत् तीन वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों पर आधारित ज़िला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- पुस्तिका मे करौली ज़िले के विकास कार्यों को भलीभाँति दर्शाया गया है। पुस्तिका में करौली ज़िले की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक स्थिति, सफलता की कहानियों के साथ-साथ फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित किये गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी।
- इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने वन विभाग के द्वारा तैयार किये गए एन्वायरमेन्ट प्लान का भी विधिवत विमोचन किया।
- कार्यक्रम के दौरान ज़िले में विभिन्न विकास कार्यों, जैसे- भवन निर्माण, स्कूल, स्मार्ट क्लासेज, विद्युत, चिकित्सा, पेयजल, कृषि सहित अन्य विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से प्रभारी मंत्री के द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार के समय में हुए विभागवार विकास कार्यों की प्रदर्शनी तैयार की गई है, जिसमें वर्तमान में हुए विकास कार्यों के साथ करौली ज़िले में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की झलक देखने को मिलेगी।
- प्रदर्शनी में चम्बल ब्रिज, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, कोविड प्रबंधन, देवनारायण आवासीय छात्रावास योजना, इंदिरा रसोई, आपदा में राहत, राजीव गांधी जल संचय योजना, पेयजल प्रबंधन, पंचायत राज, जल संसाधन, प्रशासन गाँवों एवं शहरों के संग अभियान शिविर सहित विभिन्न विकास कार्यों पर आधारित बोर्डों पर फ्लैग्स प्रदर्शित कर विकास कार्यों को दर्शाया गया है।

ज्ञानदूत 2.0 का ऑनलाइन उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 12 जनवरी, 2022 को राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिये विशेष सहायता कार्यक्रम 'ज्ञानदूत' के द्वितीय संस्करण 'ज्ञानदूत 2.0' का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में नयापन करते हुए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के उन विषयों, जो राजकीय महाविद्यालयों में संचालित हैं, के पाठ्यक्रमों के अनुसार हिन्दी भाषा में ई-कंटेंट तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके लिये कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा फिलहाल कला संकाय के 8, विज्ञान के 4 एवं वाणिज्य के 2 विषयों सहित कुल 14 विषयों में यह ई-कंटेंट तैयार करवाने की पहल की गई है।
- इसके लिये 9 राजकीय महाविद्यालयों-राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजकीय महाविद्यालय चूरू, राजकीय महाविद्यालय बांसवाडा, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय पाली, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा को विषयवार नोडल बनाया गया है।
- इस विशेष अकादमिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का ई-कंटेंट हिन्दी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसे 24 × 7 मोड पर कहीं से भी और कभी भी देखा-पढ़ा जा सकेगा। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों की विषयपरक समस्याओं का ऑनलाइन लाइव समाधान भी इस कार्यक्रम में करवाया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान कर सकेंगे। विशेषत: अभी कोविड की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनमें इस ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है।
- विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयों में तैयार करवाए जा रहे ई-कंटेंट कॉलेज शिक्षा विभाग के ज्ञानदूत चैनल पर उपलब्ध होंगे, जो कि सभी विद्यार्थियों, चाहे वे सरकारी अथवा प्राइवेट महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हों, अथवा स्वयंपाठी विद्यार्थी हों, सभी के लिये पूर्णत: नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।

नोट :

- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शासन सचिव नारायण लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान के कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षा संवर्ग में हिन्दी भाषा माध्यम के विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता के ई-कंटेंट मिलने में समस्या आती है। अत: इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग अच्छी गुणवत्ता का सब्जेक्ट कंटेंट हिन्दी भाषा में उपलब्ध करवाने जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को समझने व पढ़ने में सुविधा हो सके।

जी.एस.टी. एडवान्स्ड ऐनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 12 जनवरी, 2022 को राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त रवि जैन ने जी.एस.टी. एडवान्स्ड ऐनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने एवं करापवंचन को रोकने में तकनीकी प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्यिक कर विभाग की बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एडवान्स्ड ऐनालिटिक्स पोर्टल बनाया गया है।
- इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त (आई.टी. एंड बी.आई.यू.) शरद मेहरा ने बताया कि इस पोर्टल के द्वारा विभागीय अधिकारियों को करापवंचन एवं अन्य सूचनाएँ त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेंगी। इसके साथ ही यह पहल राज्य की राजस्व वृद्धि में अपना विशिष्ट योगदान करने में सहायक होगी।

राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में 405 पशुपालकों को किया गया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 12 जनवरी, 2022 को राजस्थान के शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्चुअली आयोजित राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में राज्य के 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री लालचंद कटारिया ने बबाई (खेतड़ी) में 10 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तैयार नवीन डेयरी संयंत्र का भी लोकार्पण किया।
- राज्य स्तर पर कृषि एवं पशुपालन सम्मानित होने वाले 2 पशुपालकों को पचास-पचास हज़ार रुपए, ज़िला स्तर पर सम्मानित होने वाली सात महिला पशुपालकों सहित 68 पशुपालकों को पच्चीस-पच्चीस हज़ार रुपए तथा पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित होने वाली 32 महिला पशुपालकों सहित 335 पशुपालकों को दस-दस हज़ार रुपए की राशि प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान की गई है।
- राज्य स्तर पर बीकानेर ज़िले के सुरेंद्र कुमार एवं सीकर ज़िले के पशुपालक सुभाष चंद को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा प्रशस्ति-पत्र तथा 50-50 हज़ार रुपए की राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
- ज़िला स्तर पर संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर ने पशुपालकों को सम्मानित किया। राज्यस्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में प्रदेश के 405 पशुपालकों को 51.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।
- शासन सचिव पशुपालन, डॉ. आरुषी मलिक ने कहा कि किसानों की तरह पशुपालकों को भी उनके क्षेत्र में मान-सम्मान मिले, इसके लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों के लिये सम्मान समारोह आयोजित करने की बजट में घोषणा की थी।
- उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन के नए आयाम स्थापित करने वाले प्रगतिशील पशुपालकों का चयन कर हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा, जिससे प्रदेश के अन्य पशुपालक भी प्रेरित हों और पशुधन विकास में अहम भागीदारी निभा सकें।

नोट :

‘अंगदान-महादान’संदेश लिखी पतंगों का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 13 जनवरी, 2022 को राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त महेंद्र सोनी ने ‘अंगदान-महादान’संदेश लिखी पतंगों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- अंगदान जागरूकता का संदेश देती ये पतंगें मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटीजन फोरम द्वारा तैयार की गई हैं। ये पतंगें मकर संक्रांति पर्व पर आसमां में चढ़ने के साथ-साथ लोगों को जागरूक भी करेंगी।
- महेंद्र सोनी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिये अंगदान की सहमति देने वालों के लाइसेंस पर ‘हार्ट का साइन’और ‘ऑर्गन डोनर’अंकित किया जाता है। इससे मृत्यु उपरांत परिजनों की सहमति से अंगदान की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- प्रदेशवासी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ अन्य माध्यमों के जरिये भी अंगदान करने की सहमति प्रदान कर अपने जीवन को अनमोल बनाएँ।
- इस अवसर पर मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटीजन फोरम की संयोजिका भावना जगवानी ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हर व्यक्ति को अंगदान जागरूकता के अभियान में जुड़कर मानवीय ज़िम्मेदारी निभानी चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिये अंगदान की सहमति देने की पहल के तहत 1 सितंबर, 2020 से लेकर 12 जनवरी, 2022 तक 2.25 लाख से अधिक स्थाई लाइसेंसधारियों द्वारा अंगदान की सहमति दी जा चुकी है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय रामगढ़ पचवारा का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 15 जनवरी, 2022 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ग्राम पंचायत बिडोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय, रामगढ़ पचवारा के भवन का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मालवीय ने कहा कि पचवारा क्षेत्र के निजामपुरा व सलेमपुरा में एक एनीकट तथा कोलीवाडा व राहुवास में एक बड़े एनीकट का निर्माण करवाया जाएगा।
- एनीकट के बनने से आसपास के ग्रामीणों, किसानों व पशुपालकों को आर्थिक सहयोग मिलेगा तथा कृषि उत्पादन भी अधिक होगा।
- समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में पचवारा को फाइव स्टार के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कन्या महाविद्यालय भवन को 10 माह में तैयार करने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने किया गांधी बधिर महाविद्यालय जोधपुर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 15 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर स्थित गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 1982 में गठित जोधपुर बधिर कल्याण समिति द्वारा 1982 में ही मूक बधिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गाँधी बधिर विद्यालय की स्थापना की गई थी।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में वर्ष 2002 में इस मूक बधिर विद्यालय को सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला। 2010 में उनके दूसरे कार्यकाल में यह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में इसे महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में मूक बधिर महाविद्यालय खोलने की घोषणा से मूक बधिर बच्चों को 12वीं से आगे की पढ़ाई में आसानी होगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले तीन साल में विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किये हैं। भर्तियों में विशेष योग्यजनों का आरक्षण बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरण भी शुरू किया गया है।
- महाविद्यालय संचालन समिति के मुख्य सलाहकार एवं पूर्व न्यायाधीश एलएन माथुर ने कहा कि इस महाविद्यालय में सांकेतिक भाषा के जानकार विशेष शिक्षकों, हियरिंग एड एवं स्मार्ट बोर्ड की मदद से मूक बधिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश के सभी ज़िलों में पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं को मिला 'एनएबीएल एक्रीडिशन'

चर्चा में क्यों?

- 17 जनवरी, 2022 को राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के तहत प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता जाँच के लिये समस्त ज़िलों में संचालित पेयजल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाओं को 'एनएबीएल एक्रीडिशन' प्रमाणीकरण मिल गया है।

प्रमुख बिंदु

- पीएचईडी में राजधानी जयपुर में मुख्यालय पर राज्यस्तरीय पेयजल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला स्थापित है, इसके अलावा अन्य 32 ज़िलों में ज़िलास्तरीय प्रयोगशालाएँ चलाई जा रही हैं। अब इन सभी 33 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र संस्था 'नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज'(एनएबीएल) से प्रमाणीकरण मिल गया है।
- देश में एनएबीएल जाँच प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिये राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र संस्था है। इसके द्वारा आईएसओ/आईईसी:17025 के तहत परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रमाणीकरण दिया जाता है।
- यह संस्था भारत सरकार में 'क्वालिटी काऊंसिल ऑफ इंडिया'के तहत स्थापित है, जो लेबोरेट्रीज के 'एनएबीएल एक्रीडिशन'के लिये थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में प्रयोगशालाओं की लीगल आईडेंटिटी, इसमें कार्यरत् मानव श्रम की संख्या के साथ ही उनकी योग्यता और अनुभव, उपकरणों के समयबद्ध केलिब्रेशन (जाँच में दक्षता की परख) आदि बिंदुओं के आधार पर 'परफॉरमेंस ऑडिट'के बाद प्रमाणीकरण करती है।
- राज्य सरकार द्वारा आमजन के स्तर पर पेयजल गुणवत्ता जाँच को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय के तहत सभी नागरिकों हेतु 16 बिंदुओं पर आधारित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण की दर 1000 रुपए से घटाकर 600 रुपए की गई है। इससे प्रदेश की सभी 'एनएबीएल एक्रीडेटेड'ज़िलास्तरीय गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाओं में लोगों को फ्लोराइड, नाईट्रेट, थर्मो टॉलरेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, टोटल कोलोफॉर्म बैक्टीरिया, आर्सेनिक, आयरन, सल्फेट, क्लोराइड, रेजिड्यूअल क्लोरीन, टोटल हार्डनेस, टोटल अल्केलिनिटी, टर्बिनिटी, टोटल डिजोल्वड सॉलिड, पीएच, कलर और ऑडर के 16 बिंदुओं पर आधारित गुणवत्ता जाँच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।
- डॉ. जोशी ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को 'हर घर जल'कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस (डब्ल्यूक्यूएमएस) प्रोगाम में पेयजल गुणवत्ता की दृष्टि से प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में 102 नई ब्लॉकस्तरीय पेयजल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की जाएंगी।
- डॉ. जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वीकृत परियोजनाओं में 'हर घर जल'कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग हेतु 11 हज़ार 343 ग्राम पंचायतों में वितरण के लिये 12 हज़ार से अधिक 'फील्ड टेस्टिंग किट'की खरीद की गई है। इस किट का उपयोग करते हुए राज्य के 43 हज़ार 323 गाँवों में गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी-विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी) के सदस्य जेजेएम में 'हर घर जल'कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता की समयबद्ध जाँच कर सकेंगे।

29वीं राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का वर्चुअल शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 18 जनवरी, 2022 को राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान ने 29वीं राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल स्पेस एवं साइंस क्लब तथा 28 फरवरी को आयोजित होने वाले राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के लोगो का भी अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर जाहिदा खान ने कहा कि विभाग द्वारा बजट 2020-21 की अनुपालना में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के लिये साइंस एंड स्पेस क्लब एवं एस्टेरॉयड खोज अभियान चलाया गया है। साथ ही राज्य में वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने एवं वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करने के लिये स्टेट आईपीआर पॉलिसी भी जारी की गई है।
- राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ज़िला व राज्य स्तर पर बच्चों के द्वारा विज्ञान पर आधारित परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जिससे बच्चों में छुपे हुए वैज्ञानिक को अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने इस राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा इसमें 10 से 14 एवं 14 से 17 वर्ष आयु के बच्चों की प्रविष्टियों के दो वर्ग बनाए गए हैं। कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तर पर प्राप्त कुल 811 प्रविष्टियों में से 87 का चयन किया गया था। इनमें से निर्णायकों द्वारा आज 30 प्रविष्टियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हेतु भेजा जाएगा।
- उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाए गए एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन की देश भर में तारीफ की गई है। विज्ञान के क्षेत्र में विभाग द्वारा लगातार किये गए नवाचारों से राज्य में विज्ञान का परचम लहराएगा तथा बच्चों में विज्ञान के प्रति अलख जग पाएगी।

'जागती जोत' के 'पंडित भरत व्यास विशेषांक' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 21 जनवरी, 2022 को राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास पर राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर की मुखपत्रिका 'जागती जोत' के 'पंडित भरत व्यास विशेषांक' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस विशेषांक के माध्यम से पंडित व्यास द्वारा रचित साहित्य के संबंध में, विशेषकर युवा पीढ़ी को महती जानकारी और प्रेरणा मिल सकेगी।
- इस अवसर पर डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मरुधरा के अमर गीतकार पं. भरत व्यास राजस्थानी भाषा से बहुत प्रेम करते थे। उनके अनेक गीतों में राजस्थान की माटी की महक है और भक्ति-शक्ति-प्रेम के साक्षात् दर्शन होते हैं।
- राजस्थान की जिन प्रतिभाओं ने प्रदेश का नाम देश-विदेश में रोशन किया है, उन बहुआयामी व्यक्तित्व व कृतित्व के धनी लोगों में पं. भरत व्यास का नाम प्रमुख है। वे एक सफल गीतकार होने के साथ-साथ बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, कथाकार व आशुकवि भी थे।
- पंडित भरत व्यास ने बीकानेर, चूरू, कोलकाता में रंगकर्मी के रूप में अपनी अनूठी छाप छोड़ी। बाद में वे मुंबई गए व अनेक फिल्मों में सैकड़ों कालजयी गीतों की रचना की। पंडित व्यास द्वारा रचित गीत- 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम' आज भी शिक्षण संस्थाओं और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना के रूप में गाया जाता है।
- उनके द्वारा लिखित अन्य गीत- जरा सामने तो आओ छलिये, आ लौट के आजा मेरे मीत, आधा है चंद्रमा, यह कहानी है दीये की और तूफान की, सहित ऐसे अनेक गीत हैं, जो इतने वर्ष बाद भी प्रासंगिक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं।
- अकादमी सचिव शरद केवलिया ने बताया कि जागती जोत के जनवरी माह के इस विशेषांक में देश के लब्धप्रतिष्ठ राजस्थानी साहित्यकारों के पं. भरत व्यास के व्यक्तित्व-कृतित्व पर आधारित आलेख, गीत, अनुवाद आदि सम्मिलित किये गए हैं।

नोट :

उद्योग मंत्री ने की 'स्वस्थ बेटी अभियान' की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के बानसूर में 'स्वस्थ बेटी अभियान' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- शकुंतला रावत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बेटियों के लिये अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'उड़ान योजना', 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' और 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' से समाज के हर वर्ग में बेटियों को सम्मान मिला है।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने इस अवसर पर अस्पताल में नवजात बालिका शिशुओं को न्यू बेबी बोर्न किट एवं माताओं को बधाई संदेश पत्र दिया और जनजागरूकता अभियान की पालना में मास्क एवं सेनीटाइजर का वितरण किया।
- इसके साथ ही उन्होंने 'स्वस्थ बेटी अभियान' को आगे बढ़ाने हेतु अस्पताल प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने एवं उचित साफ-सफाई रखने के निर्देश दिये।

राजस्थान की गौरी माहेश्वरी एवं आनंद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमे राजस्थान की गौरी माहेश्वरी एवं आनंद शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष के इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियाँ शामिल हैं। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार (7), सामाजिक सेवा (4), शैक्षिक (1), खेल (8), कला और संस्कृति (6) तथा वीरता (3) श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिये चुने गए हैं।
- इसी प्रकार वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 32 बच्चे नवाचार (9), कला एवं संस्कृति (7), खेल (7), शैक्षिक (5), वीरता (3) तथा सामाजिक सेवा (1) श्रेणियों में चुने गए हैं।
- पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2022 में राजस्थान की गौरी माहेश्वरी को कला और संस्कृति श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आनंद को शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2021 से सम्मानित किया गया।
- पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के पुरस्कार विजेता अपने माता-पिता तथा अपने-अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

नोट :

The Vision

राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 25 जनवरी, 2022 को 73वे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिये 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। राजस्थान के 5 व्यक्ति इन पुरस्कारों की सूची में शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मविभूषण', उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मभूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मश्री'पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, अर्थात् कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इत्यादि में प्रदान किये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष 'गणतंत्र दिवस' के अवसर पर की जाती है तथा आमतौर पर मार्च/अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं।
- इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंज़ूरी दी है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार (किसी जोड़ी को दिये पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है) भी शामिल हैं। इस सूची में 4 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है।
- वर्ष 2022 के लिये घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं-
  - राजस्थान से पैरालिंपियन और स्वर्ण पदक विजेता चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को खेल के क्षेत्र में और राजस्थान के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि को सिविल सेवा के क्षेत्र में 'पद्मभूषण'पुरस्कार के लिये चुना गया है।
  - इसी प्रकार पैरालिंपियन सुश्री अवनि लेखरा को खेल तथा कलाकार रामदयाल शर्मा और पटकथा लेखक चंद्रप्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में 'पद्मश्री'पुरस्कार के लिये चुना गया है।

उदयपुर के नाथद्वारा में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 28 जनवरी, 2022 को राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी एवं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने उदयपुर के नाथद्वारा में उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. उदयपुर कार्यक्षेत्र के अंतर्गत राजसमंद ज़िले की 18 चयनित समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति खोलने के संबंध में कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा वर्तमान में नई समितियों के गठन हेतु हिस्सा पूंजी को 5 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए करने का भरोसा दिया।
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर 10 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण खरीद कर समिति कार्यक्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराए पर देने के प्रावधान किये गए हैं।
- इस योजनांतर्गत प्रति समिति 10 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें से 80 प्रतिशत, यानी 8 लाख रुपए का अनुदान देय होगा एवं 20 प्रतिशत राशि संबंधित समिति द्वारा वहन की जाएगी।
- यह योजना राज्य के कृषक, विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषक, जो सीमित आय के कारण महँगे कृषि उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, के लिये प्रवर्तित की गई है।

नोट :

- योजनांतर्गत बैंक कार्यक्षेत्र की चयनित समितियों में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, थेसर आदि उपकरण क्रय कर निर्धारित तिथि से समिति के संबंधित कार्यक्षेत्र के सदस्य कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि उपकरण उचित दर पर किराए पर ले सकेंगे।
- कार्यक्रम में पूर्व में संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर वाली सहकारी समितियों, यथा मदारा, लसानी एवं सिंधु को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेन्टो वितरित किये गए, साथ ही ज़िला राजसमंद की नवगठित सहकारी समितियों यथा पाखंड, बिजनोल एवं जवासिया को पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा पाखंड, देवपुरा, जवासिया एवं बिजनोल को पैक्स डेवलपमेंट फंड से लैपटॉप का वितरण किया गया।

राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

- 30 जनवरी, 2022 को राजस्थान के परिवहन राज्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने चूरू जिले के राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर भवन का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान प्रभारी मंत्री ओला एवं सादुलपुर विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने ट्रॉमा सेंटर की शिलान्यास पटिका का अनावरण भी किया।
- इस मौके पर मंत्री ओला ने चूरू से रोहतक वाया भिवानी, सरदारशहर से दिल्ली वाया भिवानी एवं राजगढ़ से गालड़ बस सेवा शुरू करने तथा बैरासर गाँव में बस स्टॉपेज शुरू करने का आश्वासन दिया।
- विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत ट्रॉमा सेंटर के लिये कुल 6 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए लागत से भवन निर्माण किया जाएगा।

परिवहन आयुक्त ने किया डॉक्यूमेंट्री 'हर जीवन अनमोल है' को रिलीज

चर्चा में क्यों?

- 30 जनवरी, 2022 को राजस्थान के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने परिवहन भवन में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से आमजन को परिचित कराने के लिये बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 'हर जीवन अनमोल है' को रिलीज किया।

प्रमुख बिंदु

- इस डॉक्यूमेंट्री का लेखन और निर्देशन ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी व वरिष्ठ आचार्य, अस्थि रोग डॉ. अनुराग धाकड़ ने किया है। डॉक्यूमेंट्री में आवाज भी उन्होंने ही दी है।
- 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आमजन मरीज के ट्रॉमा सेंटर में पहुँचने से लेकर प्राथमिक उपचार, ऑपरेशन, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में उपलब्ध सुविधाओं के बारे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- इसका प्रसार-प्रचार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल, दूरदर्शन सहित विभिन्न माध्यमों के जरिये किया जाएगा।
- आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर टीम द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आमजन में राजकीय चिकित्सा सेवाओं के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ेगा। राजकीय चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बने कई मिथक (भ्रांतियाँ) भी दूर होंगे। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक चिकित्सकीय तकनीक से घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के बारे में भी जाना जा सकेगा।

प्रदेश में ई-दाखिल की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

- 28 जनवरी, 2022 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा ने 'ई-दाखिल पोर्टल' का उद्घाटन किया। अब प्रदेश में उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- ई-दाखिल पोर्टल पर कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेज़ों को डाउनलोड करने के लिये लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिये वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस व ई-मेल पर अलर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी।
- ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से घरबैठे ही शिकायत दर्ज करवाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके समय व धन की बचत होगी। उपभोक्ता आयोग भी आसानी से ऑनलाइन ही शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं। यदि उक्त परिवाद अन्य आयोग से संबंधित हो तो उसे संबंधित आयोग के पास आगे अग्रेषित कर सकते हैं।
- ग्रामीण उपभोक्ता, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन न हो या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, वे अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुँचाने के लिये सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) या ई-मित्र की सेवाएँ ले सकते हैं।
- ई-दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और प्रदेश में ई-दाखिल व्यवस्था को लागू करने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति प्राप्त की गई है।

दृष्टि The Vision

नोट :